दसवीं के 11 लाख विद्यार्थियों का पीएस के पास अटका प्रस्ताव

आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिल सकते है नंबर, सीबीएसई के दसवीं के विद्यार्थियों का बीस जून तक आएगा परिणाम

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं के विद्यार्थियों का परिणाम बीस जून तक घोषित किए जाने की घोषणा कर दी है। जबकि एमपी बोर्ड की दसवीं के 11 लाख विद्यार्थियों को पास करने का प्रस्ताव प्रमुख सचिव के पास अटका हुआ है। एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए जाने का निर्णय लेने की संभावना बना रही है। हालांकि पीएस के आदेश जारी करने के बाद भी दसवीं बोर्ड के विद्यार्थियों को पास करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Badri Gautam

कमेटी तैयार करेगी रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रिंसिपल और सात शिक्षकों वाली एक परिणाम समिति भी बनाने को भी कहा है। इस समिति में गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और दो भाषाओं के शिक्षक होने चाहिए। साथ पड़ोसी स्कूलों के दो शिक्षकों को समिति के बाहरी सदस्यों के रूप में चुना जाएगा।

बारहवीं बोर्ड की स्थगित है परीक्षाएं

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला छात्रों एवं शिक्षकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लिया गया है। इससे पहले सीबीएसई ने दसवीं बोर्ड के रिजल्ट के लिए अपने सभी स्कूलों को एक फार्मेट भेजा था। इस फार्मेट में स्कूल में हुए सालभर के प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि की जानकारी मांगी गई थी। इसके आधार पर ही अब फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

गलत अंक देने पर सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही

अंक देने में पक्षपात पूर्ण रवैया की शिकायत मिलने पर सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। इसके तहत स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सीबीएसई के मुताबिक सभी स्कूलों को अपने रिजल्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रिजल्ट प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जा सके। वहीं जो छात्र इस माध्यम से मिले नंबरों से खुश नहीं होंगे, उन्हें एग्जाम देकर अंक हासिल करने का मौका दिया जा सकता है।

क्लास टेस्ट, छमाही में जितने अंक मिले थे, उसी से बनेगा सीबीएसई के दसवीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट

सीबीएसई ने दसवीं के छात्रों के अंकों की गणना करने के लिए एक नई स्कीम तैयार की है। देश में महामारी की स्थिति के कारण इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बोर्ड ने स्कूलों से 11 जून तक इंटरनल मार्किंग के स्कोर अपलोड करने के लिए भी कहा है। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। शेष 80 अंक वर्षभर की विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। सीबीएसई नोटिफिकेशन में बताया कि वर्ष 2021 के लिए अधिकतम 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन से, 10 अंक यूनिट टेस्ट, 30 अंक मिड टर्म एग्जाम और 40 अंक प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर मिलेंगे।

एमपी बोर्डः मूल्यांकन को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिए जाने से 10वीं के स्टूडेंट्स, उनके पैरेंट्स चिंतित

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एमपी बोर्ड की 10वीं में मूल्यांकन को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से स्टूडेंट चिंतित हैं। उनका कहना है कि विभाग ने 10-12वीं की परीक्षाएं जून में कराने के आदेश जारी किए हैं। 10वीं को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं दी है। केवल अखबारों से जानकारी मिल रही है। एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तरह शीघ्र ही 10वीं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए, ताकि स्टूडेंट टेंशन फ्री हो। हालांकि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदरसिंह परमार ने 15 मई के बाद स्थित स्पष्ट करने

की बात कही है। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 12वीं के स्टूडेंट्स परीक्षा पास कर कॉलेजों के साथ अन्य राज्यों व विदेशों में पढ़ने जाते हैं। स्टूडेंट्स को उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से ही कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। यदि इनकी परीक्षा नहीं होगी और जनरल प्रमोशन मिलता है तो पढ़ने वाले और कम पढ़ने वाले सभी बराबर हो जाएंगे। इसलिए 12वीं की परीक्षाएं अवश्य कराई जाएंगी।

> बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। हमें तो यह भी नहीं मालूम की परीक्षाएं होगी या नहीं। यदि परीक्षाएं नहीं होंगी तो रिजल्ट किस पैटर्न पर मूल्यांकन कर तैयार किया जाएगा। सस्पेंश बढ़ने से परीक्षाओं को लेकर टेंशन हो रहा है।
>
> **मुकेश साहू,** स्टूडेंट, 10वीं

> अखबारों से पता चला था कि परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। पहले यह भी कहा गया था कि बेस्ट फाइव योजना इस बार नहीं रहेगी। परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं मिले हैं। बेस्ट फाइव को लेकर भी कुछ तय नहीं है। जो पढ़ा था, वह भी भूल गया है। जल्दी इस संबंध में आदेश जारी होना चाहिए।
>
> **हेमराज दांगी,** स्टूडेंट, 10वीं

> सीबीएसई ने 10वीं के मूल्यांकन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन एमपी बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। दोनों ही कक्षाओं के छात्र परेशान हैं। बोर्ड को इस संबंध में आदेश जारी कर छात्रों का टेंशन शीघ्र दूर करना चाहिए।
>
> **नवीन तिवारी,** पैरेंट, चूना भट्टी

> एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी है। वैल्युएशन किस आधार पर होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। 12वीं की परीक्षाएं अवश्य होंगी, क्योंकि इन बच्चों को स्कूल छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। 15 मई के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।
>
> **इंदर सिंह परमार,** राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा

Badri Gautam

नए सत्र में भी स्कूलों को नहीं मिलेंगे नियमित शिक्षक, विभाग ने बढ़ाई अतिथियों की सेवाएं

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

स्कूल शिक्षा विभाग पात्रता परीक्षा लेने के तीन साल बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाया है। जो हालात हैं, उसके अनुसार अगले सत्र में भी नियमित शिक्षक नहीं मिल पाएंगे और अतिथियों से ही काम चलाया जाएगा।

शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट में आए पात्र शिक्षकों का दो बार वेरिफिकेशन शुरू होकर रुकने और अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ने से एक बार फिर अभ्यर्थी मायूस हो गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 70 हजार से अधिक शिक्षकों की कमी

Badri Gautam

है। तीन साल से वर्ग 1 व 2 की पात्रता परीक्षा पास कर अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना के नाम पर दूसरी बार शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन बीच में रोक दिया है। इसके चलते लगभग 50 फीसदी अभ्यर्थी फिर अटक गए हैं।

अतिथियों की भर्ती से असमंजस की स्थिति: लोक शिक्षण संचालनालय ने 30 अप्रैल को एक आदेश जारी कर सत्र 2020-21 के लिए पुनः अतिथि शिक्षकों को रखने की बात कही है। इससे इस सत्र में स्थाई शिक्षकों की भर्ती पर असमंजस बना हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि 5 मई से सत्यापन प्रक्रिया फिर शुरू होगी। लेकिन यह संभव नहीं दिख रहा है।

सरकार को अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाने की जगह समस्त रिक्त पदों पर स्थाई शिक्षकों की भर्ती इसी सत्र में पूर्ण करना चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार हो सकेगा।

रंजीत गौर, प्रदेश संयोजक,
शिक्षक पात्रता संघ, मप्र

फिर उठा अनुकंपा नियुक्ति का मामला... शिक्षक संघ का आरोप

अगली सुनवाई से पहले धड़ाधड़ की गईं नियुक्तियां, अब मामला ठंडे बस्ते में डाला

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

कोरोना संक्रमण काल में एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में राज्य शिक्षक संघ ने विभाग पर आरोप लगाए हैं कि हाईकोर्ट में अनुकंपा नियुक्त के मामले में लगी अवमानना याचिका को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अगली सुनवाई से पहले धड़ाधड़ नियुक्तियां की गईं। अब सुनवाई होते ही इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। संघ ने मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि आश्रितों को सहारा मिल सके।

संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि विगत जनवरी फरवरी माह में अचानक ही लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश आ गया कि जितने भी अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। इसके लिए जिलों में शिविर लगने लगे। जिलों से प्रयोगशाला सहायक, भृत्य पद पर नियुक्ति के आर्डर भी 10-20 की संख्या में निकलने लगे। शिक्षा मंत्री का तो सोशल मीडिया में बयान भी आ गयाए, ऐसा लगा शिक्षा विभाग मानवीय और संवेदनशील हो गया है। लेकिन बाद में पता चला कि कि एक अनुकंपा मामले में अवमानना लगी है, इसीलिए अगली पेशी से पहले कुछ किया है यह दिखाने के लिए विगत 10 वर्षों से लगी नींद टूटी है। उसके बाद पेशी हुई तो हाईकोर्ट की कार्रवाई से बच गए अब फिर मामला जहां के तहां रुक गया है।

पेशी के बाद नहीं हुआ ऑर्डर

यादव का कहना है कि जिस दिन से पेशी हुई उस दिन के बाद से एक भी अनुकंपा नियुक्ति का आर्डर किसी भी जिले द्वारा नहीं किया गया है, जिनके आर्डर नहीं हुए वो चक्कर काट रहे हैं। यादव ने लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत से मांग की है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी अनुकंपा प्रकरणों में नियुक्तियां दी जाएं।

शिक्षक पात्रता संघ ने कहा : नए शिक्षण सत्र में भी स्कूल अतिथियों के भरोसे, स्थाई शिक्षक भर्ती पर असमंजस

प्रदेश में के सरकारी स्कूलों में लगभग 70 हजार से अधिक शिक्षकों की कमी है। तीन साल से वर्ग 1 व 2 की पात्रता परीक्षा पास कर अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसी बीच अब लोक शिक्षण संचालनालय ने 30 अप्रैल को एक आदेश जारी कर सत्र 2020-21 के लिए पुनः अतिथि शिक्षकों को रखने की बात कही है। जिससे इस सत्र में स्थाई शिक्षकों की भर्ती पर असमंजस बना हुआ है। मामले मे शिक्षक पात्रता संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर का कहना कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय विभाग द्वारा लगभग 30,000 शिक्षकों की स्थाई भर्ती प्रक्रिया को कोरोना संकट के कारण बीच में ही स्थगित कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विगत 2 वर्षों से चल रही हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। नतीजन शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों परेशान हैं। गौर ने मांग की है कि सरकार को अतिथि शिक्षकों की जगह समस्त रिक्त पदों पर स्थाई शिक्षकों की भर्ती इसी सत्र में पूर्ण करना चाहिए, जिससे कि प्रदेश की शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। हालांकि लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों का कहना है कि 5 मई से सत्यापन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना कर्फ्यू के कारण 5 मई से सत्यापन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होना संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।

2017 में शुरू हुई थी प्रक्रिया

शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2017 में शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट तैयार किया था। 11 सितंबर 2018 को जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जहां 17 हजार पद जारी किए गए हैंए इसमें से पहले चरण में केवल 15ए000 पदों के लिए ही मेरिट लिस्ट जारी की गई। वहीं वर्ग.2 के 5ए670 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई है। इन दोनों वर्गों के 20ए670 अभ्यर्थियों का सत्यापन होना है। पिछले वर्ष 2020 में शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया जुलाई में रोक दी गई। अब 1 अप्रैल से दोबारा सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गईए लेकिन 15 दिन भी पूरे नहीं हुए इसे कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया है।

Badri Gautam

निजी स्कूलों का अटका एक साल से फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा डीपीसी कार्यालयों में बिगड़ा सिस्टम

Badri Gautam

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के तहत मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान पिछले 1 साल से नहीं हो रहा है। यह आरोप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लगाया है। इधर राज शिक्षा केंद्र में अधिकारियों का कहना है कि नियम के अनुसार पूरा काम हो रहा है। इसकी नियमित समीक्षा हो रही है।

स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद स्कूल संचालकों को फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने हेतु तरह-तरह के जतन करने पड़ हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि सत्र के अंत तक भुगतान हो जाना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का आरोप है कि भुगतान को सही समय पर करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने भी अनेक नियम बनाए, परंतु यह नियम केवल फाइल की शोभा बनकर रह गए हैं। इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के किसी जिले में नहीं हो रहा है। इसका परिणाम स्कूल संचालक भुगत रहे बच्चों को 3 से लेकर 4 साल पढ़ाने के बाद भुगतान के लिए तरह-तरह के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। पिछले 1 वर्ष से पूरा प्रदेश कोविड-19 की मार झेल रहा है। स्कूलों में मार्च के बाद से आज दिनांक तक फीस जमा नहीं हुई है। आरोप है कि स्कूल संचालक खुद के पैसे जो राज्य शिक्षा केंद्र के पास पड़े हैं। उनके भुगतान के लिए रोज नए-नए आवेदन ज्ञापन दे रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश के समस्त डीपीसी एवं राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। खुद के बनाए हुए नियम इन्हें याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र हमें कोई सहायता आर्थिक पैकेज भले न दे, परंतु हम संचालकों के खून पसीने मेहनत की राशि समय से मिल जाए।

इसके लिए जब संचालक डीपीसी कार्यालय जाता है तो भुगतान तो दूर वहां बैठे हुए लोग लेन-देन की बात करने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भयावह है। राज शिक्षा केंद्र में अधिकारियों का कहना है कि फीस प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान समय से हो रहा है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।

राजधानी में 3,000 से अधिक बच्चों का भुगतान शेष

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि राजधानी भोपाल का छोटा सा उदाहरण है। अभी वर्तमान स्थिति को देखें तो भोपाल में वर्ष दो हजार सोलह सत्रह के 182 प्रपोजल है। इनमें करीब 1197 बच्चे इनका भुगतान होना है। अजीत सिंह के अनुसार वर्ष दो हजार सत्रह अठारह में 255 प्रपोजल हैं, इसमें 3336 बच्चों का भुगतान शेष है। भोपाल जिले में 15 जुलाई 2020 के बाद 1 माह से अधिक समय हो गया। किसी एक भी बच्चे का भुगतान नहीं हुआ है। यहां पर हालाकि लगातार यह भरोसा मिल रहा है कि फीस भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मांग करता है कि आरटीई का भुगतान राजधानी में भी शीघ्र हो ताकि यहां प्राइवेट स्कूल संचालकों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके।

एक दिन में निरस्त हुआ कोरोना योद्धा वाला आदेश

अब दूसरा संशोधित आदेश जारी कर सकता है जिला प्रशासन

जागरण, रीवा। जिला प्रशासन ने 40 विभागों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने वाला आदेश निरस्त कर दिया है। कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी. ने इस बाबत गत 1 मई को आदेश जारी किए थे। उक्त आदेश में कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने दूसरा आदेश जल्द जारी करने जैसी कोई बात नहीं लिखी है। फिर भी सम्भावना जताई जा रही है कि राज्य शासन के निर्देश पर शीघ्र जिला प्रशासन द्वारा नवीन आदेश प्रसारित किए जायेंगे।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को रोकने जो सरकारी कर्मचारी निरंतर काम कर रहे हैं, उन्हें कोरोना योद्धा घोषित करने की योजना सरकार ने चलाई है। अप्रैल 2020 में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है। इस योजना में कलेक्टर उन कर्मचारियों को शामिल कर सकते हैं, जो कोरोनाकाल में सेवाएं दे रहे हैं। इस योजना के तहत विगत 30 अप्रैल 2021 को कलेक्टर ने आदेश जारी किया था, जिसमें जिले के 40 विभागों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की पात्रता दी जा रही थी। जारी आदेश 31 मई तक प्रभावी होना उक्त पत्र में उल्लेखित रहा, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।

इन विभागों का नाम रहा शामिल

निरस्त हुए आदेश में कलेक्टर ने राजस्व, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की पात्रता में शामिल किया था। इसके अलावा नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, बिजली विभाग, आबकारी विभाग, नगर सेना, परिवहन विभाग, खनिज विभाग के कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा की पात्रता देना पत्र में उल्लेखित रहा। ऐसे ही सहकारिता, कृषि, खाद्य विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण, मत्स्य विभाग, जल संसाधन विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, श्रम विभाग, हाउसिंग बोर्ड, भू-अभिलेख सहित कुछ अन्य विभागों का जिक्र 30 अप्रैल को जारी आदेश में किया गया था।

Badri Gautam

शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करे सरकार

मुरैना, ब्यूरो

कोविड ड्यूटी के दौरान प्रदेश में हजारों शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं और कई शिक्षकों की मौत हो चुकी है, लेकिन शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं मिला है। अन्य विभागों की तरह कोरोना महामारी में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को कोरोना योद्धा योजना में शामिल किया जाये। यह मांग मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. नरेश सिंह सिकरवार ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में की है।

जिलाध्यक्ष डॉ. सिकरवार ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी शिक्षक कोरोना ड्यूटी कर अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी तक 400 से अधिक शिक्षक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और 5000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक शिक्षकों को कोरोना योद्धा नहीं माना है। ऐसे में न तो उन्हें इलाज में सरकारी मदद मिल पा रही है और न ही मुआवजा दिया जा रहा है।

उन्होंने मांग की कि सरकार कोरोना ड्यूटी कर सेवा दे रहे शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। मांग करने वालो में विमलेश यादव, रामबरन सिंह पायथा, रामावतार सिंह बागचीनी, रघुराज परमार, जगमोहन सेमिल, सतंजय मिश्रा, महेश कुमार गुप्ता, जगदीश शर्मा आदि शामिल हैं।

Badri Gautam

शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

पूर्व मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भिण्ड, ब्यूरो।

पूर्व मंत्री एवं लहार विधायक डॉ. गोविन्द सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना की रोकथाम में लगे शिक्षकों एवं अध्यापकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर संघ के जिला संयोजक जानकी नंदन समाधिया, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह कुशवाह और मार्गदर्शक प्रशांत त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह से उनके निवास पर जाकर भेंट की। संघ के पदाधिकारियों ने डॉ. सिंह को एक पत्र सौंपकर बताया कि मप्र में कोरोना महामारी की रोकथाम सहित अन्य व्यवस्थाओं में अध्यापकों एवं शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें कई शिक्षक कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। जिससे उनके परिवारों के लालन-पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। अतः कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे सभी शिक्षकों व अध्यापकों को कोरोना योद्धा घोषित कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्राचार कर राज्य सरकार से इस संबंध में आदेश जारी कराने के लिए प्रयास करें। इस पर डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के समय ड्यूटी दे रहे शिक्षकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश राज्य सरकार से जारी करने की अनुशंसा की है।

Badri Gautam

अस्पतालों के साथ अब स्कूल में मुनाफे का अवसर

पिछले साल जो रियायत दी उसकी कसर निकालेंगे

100% बढ़ी स्कूल फीस

पहले 39630 ₹ ट्यूशन फीस थीं एक स्कूल की

अब 80820 ₹ सालाना फीस कर दी स्कूल ने

ऑनलाइन कक्षा के बहाने स्कूल डाल रहे फीस भरने का दबाव

इंदौर | DBStar

कोरोना काल में अस्पतालों के भारी-भरकम बिल के साथ ही अब आपदा में मुनाफे के अवसर की बारी निजी स्कूलों की है। शहर के कई निजी स्कूलों ने संकट के इस दौर में बच्चों के माता-पिता को राहत देने के बजाय नए शिक्षा सत्र की ट्यूशन फीस नौ से 103 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। जबकि कायदे से फीस में 15 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय प्रशासन के आदेश से स्कूल बंद हैं। फिर भी ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर ऑनलाइन ही बढ़ी हुई फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने कम फीस को लेकर पिछले लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किए थे, जो इस लॉकडाउन में लागू नहीं होते। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि स्कूल यदि फीस बढ़ाकर ऑनलाइन क्लास का दबाव बना रहे हैं तो हम गाइडलाइन जारी करवाएंगे?

कुछ स्कूलों ने 2021-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए पिछले साल की तुलना में फीस में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। कहीं चार तो कहीं एक किस्त में यह फीस ऑनलाइन जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। जो अभिभावक फीस जमा नहीं करवा रहे, उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं की लिंक तक नहीं भेजी जा रही है। अभिभावकों की शिकायत पर डीबी स्टार ने सिका स्कूल स्कीम 78, आईएसबी (इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे) बायपास के पास, विद्यांजलि स्कूल राजेंद्र नगर, गोल्डन स्कूल, सेंट पॉल स्कूल और एनडीपीएस खंडवा रोड के पिछले और नए शैक्षणिक सत्रों की फीस का आकलन किया। इसमें पता चला है कि ज्यादातर स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस का स्ट्रक्चर तक जारी कर दिया है।

सरकार का आदेश आया तो समायोजित कर देंगे फीस

जो भी फीस बढ़ाई है, वह सरकारी नियमों के हिसाब से है। हालांकि हमारा शैक्षणिक सत्र इस बार जून से शुरू होगा। तब तक यदि सरकार की तरफ से किसी तरह का आदेश आया तो हम जमा करवाई गई अतिरिक्त फीस समायोजित कर देंगे।
फादर सीबी जोसेफ, प्राचार्य सेंट पॉल स्कूल

DBStar EXCLUSIVE छह स्कूलों की पड़ताल की तो सामने आई महंगाई

स्कूल	2020-21	2021-22	कक्षा	बढ़ोतरी
एनडीपीएस	39630	80820	1-8	103.9%
सिका	38500	48900	1-5	27%
सेंट पॉल	42620	51880	नर्सरी	21%
गोल्डन स्कूल	40000	50800	1-8	27%
आईएसबी	24000	30000	1-5	25%
आईएसबी	27000	33000	6-8	22%
आईएसबी	34000	40000	9-10	17.6%
विद्यांजलि	25500	28000	केजी	9.8%

पालकों की पीड़ा- अधिकारी कहते हैं हम तो कोरोना व्यवस्था में लगे हैं

माणिकबाग निवासी आरसी ओझा का कहना है कि उनके बेटे की सालाना फीस नौ हजार रुपए बढ़ा दी गई है। स्कूल यह फीस ऑनलाइन जमा कराने को लेकर दबाव बना रहे हैं। महालक्ष्मी नगर की राजश्री दिवाकर के मुताबिक उनके दो बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। दोनों स्कूलों ने 2021-22 की फीस सात-सात हजार रुपए बढ़ा दी है। इसी तरह कई अभिभावक फीस बढ़ोतरी पर परेशान हैं। इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी रवि सिंह से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कोरोना व्यवस्था में व्यस्त होने का हवाला देकर मिलने से ही इनकार कर दिया।

गजट कहता है- सरकारी मंजूरी के बिना नहीं बढ़ा सकते 10% से ज्यादा फीस

सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिसंबर 2020 में जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नया शिक्षा सत्र शुरू होने के दौरान स्कूलों को 10 फीसदी तक फीस बढ़ाने की अनुमति होती है। हालांकि यह फीस वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के कारण स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाए थे। उलटा, सरकार ने कई तरह के शुल्क हटवा दिए थे। इस बार सरकार ने फीस को लेकर किसी तरह के आदेश जारी नहीं किए हैं। लिहाजा, लगभग सभी स्कूलों ने अपनी फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी बिना अनुमति ही कर दी है।

1 जिला/राज्य समिति द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना का परीक्षण और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की प्रक्रिया :- (1) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (2) के उप खण्ड (चार) अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना मे वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो निजी विद्यालय ऐसी प्रस्तावित फीस वृद्धि करने हेतु सक्षम होगा। निजी विद्यालय द्वारा प्रपत्र तीन मे प्रस्तुत ऐसी

2 (2) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड के उपखण्ड (चार) के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना मे 10% से अधिक किन्तु 15% या उससे कम है, तो जिला समिति प्रस्तावित फीस संरचना पर 45 कार्यदिवसों के भीतर निर्णय लेगी।

3 (3) नियम 3 के उपनियन (2) के खण्ड के उपखण्ड (चार) के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना मे वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 15% से अधिक है, तो जिला समिति 07 कार्यदिवसों के भीतर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव को राज्य समिति को प्रेषित करेगी।

सबने साध ली चुप्पी बढ़ती फीस पर सवाल किया तो

फीस बढ़ोतरी को लेकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आपको इस संबंध में जो भी बात करना है, मेरे ऑफिस में कीजिए। वहां जो भी स्टाफ होगा, वही जवाब देगा।
अनिल व्यास, उप प्राचार्य सिका स्कूल स्कीम 78

स्कूल में फीस वृद्धि को लेकर मैं फिलहाल कोई बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त हूं। आप तीन-चार दिन बाद संपर्क करना। संभव हुआ तो बात करूंगा।
गोपाल मारवाल, डायरेक्टर एनडीपीएस

मैं स्कूल का मैनेजमेंट देखती हूं, लेकिन मीडिया से बात नहीं करती। यह काम अमित शर्मा देखते हैं। स्कूल में फीस बढ़ाने को लेकर मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगी। आप उन्हीं से बात कर लीजिए।
सिमरन सिंह, असिस्टेंट मैनेजर आईएसबी
(अमित शर्मा का मोबाइल नंबर 7869479663 बंद मिला।)

विद्यांजलि स्कूल के फोन नंबर 07312892780 और गोल्डन स्कूल के फोन नंबर 09669296698 पर दो दिन तक संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। जिला शिक्षा अधिकारी रवि सिंह के मोबाइल नंबर 9425391052 पर भी दो दिन तक लगातार कॉल किए, जो उन्होंने रिसीव नहीं किए।

सीधी बात पवन जैन, एडीएम — फीस को लेकर जारी करवाएंगे गाइडलाइन

शहर के कुछ निजी स्कूलों ने सालाना फीस में 103 फीसदी तक की बढ़ोतरी क्यों कर दी है?
- अभी तो स्कूल बंद है। इसलिए फीस बढ़ोतरी का सवाल ही नहीं उठता।

लेकिन स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं। अभिभावकों को ऑनलाइन ही फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा क्यों?
- स्कूल, अभिभावकों की मर्जी से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं तो अलग बात है। अभिभावकों को शिकायत करना चाहिए।

पालकों का कहना है कि उन्होंने शिकायत करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है?
- यदि निजी स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है तो हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर इस संबंध में गाइडलाइन जारी करवाएंगे।

Badri Gautam

सीबीएसई बोर्ड : 12वीं के छात्रों के लिए प्रश्न बैंक जारी, 1 जून को आ सकती है परीक्षा की तिथि

अजमेर | सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के लिए बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश कोर, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकानोमिक्स, केमिस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस और इंफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस के प्रश्न बैंक जारी किए हैं। 1 जून को परीक्षा तिथि घोषित हो सकती है। 10वीं के नतीजे 20 जून को आएंगे।

Badri Gautam

आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं : • सीबीएसई की वेबसाइट cbseacademic.nic.in या cbse.nic.in के होम पेज 'question bank' टैब पर कक्षा 12 पर क्लिक करें। • स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा। • यहां से विद्यार्थी संबंधित विषय का प्रश्न बैंक पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा आयोजन से 15 दिन पहले सीबीएसई परीक्षा तिथि कार्यक्रम जारी करेगा। ताकि छात्रों को परेशानी न हो।

भास्कर EXPLAINER • सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट तय करने की नीति जारी की है; जानिए, नतीजे तय करने की इस नई व्यवस्था से जुड़े हर सवाल का जवाब

छठा विषय लेने वालों को सर्वाधिक अंक वाले 3 विषयों के औसत अंक मिलेंगे

सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट तय करने की नीति जारी कर दी। इसमें रिजल्ट कमेटी बनाने के साथ-साथ रेफरेंस ईयर का क्राइटेरिया भी बताया गया, लेकिन छात्रों व अभिभावकों के मन में इससे जुड़े तमाम सवाल हैं, जिनके जवाब बोर्ड नोटिफिकेशन व बोर्ड एक्सपर्ट से बातचीत करके बता रहे हैं अनिरुद्ध शर्मा...

▪ **10वीं के नतीजे स्कूल टेस्ट, छमाही व प्री-बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर तय होने हैं। किसी स्कूल में तीनों श्रेणियों में एक से ज्यादा टेस्ट हों तो क्या होगा?**
ऐसी स्थिति में रिजल्ट कमेटी हर श्रेणी के सभी टेस्ट व परीक्षाओं के वेटेज तय कर सकती है। इसमें औसत अंक या हर श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ अंक लिए जा सकते हैं।

▪ **किसी स्कूल में सिर्फ ऑनलाइन मिड टर्म एक्जाम, किसी में टेस्ट व हाफ ईयरली एक्जाम ऑनलाइन और प्री-बोर्ड ऑफलाइन हुआ। यानी 80 अंक के लिए तय श्रेणियों के नतीजे ही उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या होगा?**
ऐसे में रिजल्ट कमेटी मूल्यांकन के लिए व्यापक मानकों के आधार पर विचार करेगी और 80 अंक के मानदंड तय करेगी।

▪ **किसी ने छठे विषय के रूप में आर्ट, म्यूजिक, तीसरी भाषा या अन्य विषय लिया था, उसे कितने अंक मिलेंगे?**
सर्वाधिक अंक वाले तीन विषयों के औसत अंक छठे विषय में मिलेंगे।

▪ **क्या कोई अभिभावक रिजल्ट कमेटी की मीटिंग की निगरानी कर सकता है?**
नहीं, यह बैठक गोपनीय होगी। कमेटी के मिनट्स रेशनल डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे।

▪ **कोई दिव्यांग छात्र टेस्ट व परीक्षा में शामिल नहीं हो सका, तो क्या होगा?**
उनका मूल्यांकन पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट से होगा।

▪ **कुछ स्कूलों में एक या दो बार ही बोर्ड परीक्षा हुई है, उनका क्या होगा?**
दो साल में बेहतर वाले को और एक साल में उसी वर्ष को रेफरेंस ईयर माना जाएगा।

▪ **नई व्यवस्था में ग्रेस मार्क मिलने की गुंजाइश कितनी होगी?**
स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए इंटरनल असेसमेंट और रिजल्ट कमेटी द्वारा तय किए गए अंकों की गणना के आधार पर जब बोर्ड रिजल्ट की गणना करेगा, तब बोर्ड ग्रेस मार्क की नीति भी लागू करेगा।

▪ **क्या छात्रों को कंपार्टमेंट एक्जामिनेशन का मौका मिलेगा?**
20 जून को रिजल्ट घोषित करने के बाद बोर्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन कंपार्टमेंट एक्जाम आयोजित कर सकता है। इसके नतीजे आने तक इन छात्रों को 11वीं कक्षा में बैठने की अनुमति होगी।

▪ **कोई छात्र सख्त मार्किंग के चलते शत-प्रतिशत अंक नहीं ला पाया, वहीं अन्य स्कूल में छात्रों को पूरे नंबर मिले, क्योंकि उनका पेपर व मार्किंग अलग थे। इनका फेयर रिजल्ट कैसे बनेगा?**
इसके लिए 3 साल की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के सर्वश्रेष्ठ ओवरऑल प्रदर्शन को रेफरेंस ईयर के तौर पर माना जाएगा। जैसे 2017-18 में ओवरऑल प्रदर्शन 72%, 2018-19 में 74% और 2019-20 में 71% फीसदी था तो 2018-19 को रेफरेंस ईयर माना जाएगा। बोर्ड स्कूलों को चार्ट भेजेगा, उसी आधार पर अंक तय होंगे। चूंकि औसत अंक से 2 कम या ज्यादा देने की छूट होगी, यानी किसी विषय के औसत 98 हों, तभी 100 अंक की संभावना है।

▪ **जिन स्कूलों के छात्र पहली बार बोर्ड परीक्षा देने वाले थे, उनके पास तो कोई रेफरेंस ईयर ही नहीं है, तब क्या होगा?**
ऐसी स्थिति में बोर्ड पिछले दो वर्ष में उस स्कूल के जिले, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के बेहतर ओवरऑल औसत अंकों को रेफरेंस ईयर के तौर पर लेंगे। सीबीएसई यह डेटा सभी स्कूलों को उनके समूह के मुताबिक यानी नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, निजी व सरकारी स्कूल श्रेणियों में मुहैया कराएगा।

▪ **यह कैसे तय होगा कि रिजल्ट कमेटी ने जो अंक तय किए हैं, वे उचित हैं?**
बोर्ड इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं। यदि स्कूल द्वारा दिए गए अंक बोर्ड के चार्ट से मेल नहीं खाएंगे तो कमेटी को अंकों में संशोधन करना होगा।

▪ **कमेटी बोर्ड के चार्ट के हिसाब से अंक देने में अक्षम रही हो क्या होगा?**
ऐसे में 9वीं के प्रदर्शन को वेटेज दे सकते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट हो सकता है।

▪ **ऑनलाइन पोर्टल पर नंबर अपलोड करने के बाद उसमें संशोधन संभव है?**
बिल्कुल नहीं, इंटरनल अंक या रिजल्ट कमेटी द्वारा अपलोड अंक अंतिम होंगे।

▪ **क्या अंकों का सत्यापन, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने या पुनर्मूल्यांकन का मौका भी होगा?**
यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड की कॉपियां सभी छात्रों को स्कूलों द्वारा दिखाई गई हैं या दे दी गई हैं। ऐसे में सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी।

▪ **प्राइवेट/पत्राचार/कंपार्टमेंट का दूसरा मौका कब मिलेगा?**
इस पर जल्द ही विस्तृत नीति जारी करेंगे।

Badri Gautam

अब सीबीएसई एफीलिएशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून

सिटी रिपोर्टर| सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने एफीलिएशन के लिए स्कूलों के अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब स्कूल 30 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई लेट फीस भी नहीं देनी होगी। इसके साथ ही बोर्ड ने अपग्रडेशन और एक्सटेंशन के लिए भी समय-सीमा बढ़ा दी है। नोटिफिक्केशन के मुताबिक, कोरोना के कारण बने हालातों पर विचार करने और समीक्षा करने के बाद बोर्ड ने नए एफीलिएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है।

Badri Gautam

नेशनल पोर्टल : महिलाओं की शिक्षा के मामले में मध्यप्रदेश देश में 28वें पायदान पर

प्रदेश में 15 से 49 वर्ष की 59.4% महिलाएं ही शिक्षित

हमसे बेहतर छत्तीसगढ़, वहां की 66.3 फीसदी महिलाएं शिक्षित हैं

भोपाल/ग्वालियर • डीबी स्टार

महिलाओं की शिक्षा के मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि प्रदेश में 15 से 49 आयु वर्ग की सिर्फ 59.4 फीसदी महिलाएं ही शिक्षित हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं, बल्कि ये आंकड़े हैं भारत सरकार के नेशनल पोर्टल के। इसके हिसाब से महिलाओं की शिक्षा के मामले में मध्यप्रदेश देशभर में 28वें स्थान पर है, जबकि सबसे अच्छी स्थिति हमेशा की तरह केरल राज्य की ही है। जहां 49 वर्ष के आयु वर्ग की 97 फीसदी से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हैं। वहीं, सबसे खराब हालात बिहार और राजस्थान के हैं। इन राज्यों में 49.6 फीसदी महिलाएं ही शिक्षित हैं, जबकि शासन द्वारा बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद इनका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है।

शहर के मुकाबले ग्रामीण महिला शिक्षा का प्रतिशत सिर्फ 61

इसके अलावा मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 61 फीसदी महिलाएं शिक्षित हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में 81 फीसदी महिलाएं शिक्षा लेकर जीवन यापन कर रही हैं।

राज्यवार शिक्षित महिलाओं की स्थिति

राज्य	शिक्षित महिलाएं	राज्य	शिक्षित महिलाएं	राज्य	शिक्षित महिलाएं
केरल	97.9	नागालैंड	81	ओडिशा	67.4
मिजोरम	93.5	त्रिपुरा	80.4	छत्तीसगढ़	66.3
गोवा	89	महाराष्ट्र	80.3	अरुणाचल प्रदेश	65.6
हिमाचल प्रदेश	88.2	तमिलनाडु	79.4	तेलंगाना	65.2
सिक्किम	86.6	उत्तराखंड	76.5	आंध्र प्रदेश	62.9
मणिपुर	85	हरियाणा	75.4	उत्तरप्रदेश	61
अंडमान निकोबार	84.1	गुजरात	72.9	मध्यप्रदेश	59.4
मेघालय	82.8	कर्नाटक	71.7	झारखंड	59
दिल्ली	81.8	पश्चिम बंगाल	71	राजस्थान	56.5
पंजाब	81.4	असम	71.8	बिहार	49.6
		जम्मू काश्मीर	69		

शहरी क्षेत्रों में 20 फीसदी ज्यादा महिलाएं शिक्षित

नेशनल पोर्टल पर जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अच्छा है। जहां शहरी क्षेत्रों का औसत 43.6 फीसदी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का औसत महज 61.3 फीसदी ही है यानी गांवों की तुलना में शहर की 20 फीसदी ज्यादा महिलाएं शिक्षित हैं।

राष्ट्रीय औसत से भी मध्यप्रदेश है 9% पीछे

आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश देश के अंतिम पांच शहरों में तो है ही। इसके साथ ही राष्ट्रीय औसत से भी काफी पीछे चल रहा है। जहां राष्ट्र का औसत 68 फीसदी है वहीं प्रदेश का औसत 59.6 फीसदी ही है यानी राष्ट्रीय औसत से भी 9 फीसदी कम। इसी क्रम में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों का औसत राष्ट्रीय औसत से भी 13 फीसदी ज्यादा है।

Badri Gautam

श्रमोदय विद्यालय में बुला रहे बैठक के लिए, शिक्षक नाराज

इंदौर | DBStar

इंदौर सहित पूरे प्रदेश में 31 मई तक स्कूलों में पढ़ाई बंद है। ऑनलाइन कक्षाएं तक नहीं चल रही हैं। इसके बावजूद धार रोड स्थित श्रमोदय विद्यालय में शिक्षकों को प्राचार्य द्वारा बैठक के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। 1 मई को ही करीब 40 शिक्षकों को बैठक के नाम पर दो घंटे तक इकट्ठा बैठाया गया। 3 मई को भी बैठक बुलाई है। प्राचार्य स्कूल खुलने पर बच्चों की पढ़ाई, उनकी परीक्षा आदि पर बात करने के लिए यह बैठक बुला रहे हैं। इस पर शिक्षकों को आपत्ति है। उनका कहना है कि कोरोना के संक्रमण काल में इस तरह बैठक करना ठीक नहीं है। इसे वर्चुअल भी किया जा सकता है। शिक्षकों ने इस संबंध में प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि यह श्रमोदय विद्यालय संचालन समिति मप्र के सचिव का आदेश है। आपको स्कूल आना ही है। श्रमोदय विद्यालय में पहले सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही थीं। अब बच्चों को घर भेजकर छात्रावास भले बंद कर दिए हैं लेकिन शिक्षकों की बैठकों का दौर जारी है। 1 मई को सुबह 10 बजे से यहां के पुस्तकालय कक्ष में 40 शिक्षकों की बैठक ली गई थी। यह बैठक सिर्फ शिक्षकों को किसी बहाने से स्कूल बुलाने के लिए ली गई थी। इन्हीं में से कई शिक्षक पिछले दिनों ऐसी ही बैठकों के कारण कोरोना संक्रमित हुए थे।

श्रमोदय विद्यालय में 1 मई को भी हुई बैठक से बाहर निकलते शिक्षक।

Badri Gautam

बंगाल से लौटकर करूंगा कार्रवाई

मैं फिलहाल विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए पश्चिम बंगाल आया हूं। इसलिए इंदौर के श्रमोदय विद्यालय में शिक्षकों की बैठक बुलाए जाने को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब यहां से लौटने के बाद ही इस मुद्दे को लेकर कोई कार्रवाई कर पाऊंगा।

छोटे सिंह, सचिव श्रमोदय विद्यालय संचालन समिति मप्र

मेहरबानी... विभाग ने माना दोषी, लोकायुक्त में चल रही जांच

दो करोड़ के घोटाले में आरोपी अफसर को पीआईयू में प्रमोशन

भोपाल/इंदौर • डीबी स्टार

इंदौर जिले के चार मॉडल स्कूलों में करीब दो करोड़ रुपए के घटिया निर्माण के मामले में आर्थिक अनियमितता का दोषी मिलने के बाद पीआईयू (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) के जिस तत्कालीन संभागीय परियोजना यंत्री आनंद प्रकाश राणे पर कार्रवाई होना थी, उसे पदोन्नत कर पीआईयू भोपाल का सहायक परियोजना संचालक बना दिया गया। जबकि लोकायुक्त संगठन इस मामले की जांच ही कर रहा है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि मॉडल स्कूलों में अमानक और अधूरे निर्माण कर भवन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिए हैं। अमानक निर्माण को लेकर प्रत्येक स्कूल में 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ। शिकायत पर विभाग ने जॉइंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर केके लच्छे से जांच कराई, तो सही पाई गई। विभागीय जांच की यह रिपोर्ट शासन और विभाग के भोपाल मुख्यालय को भी भेजी गई। पीडब्ल्यूडी के अवर सचिव ने 4 जनवरी 2019 को परियोजना संचालक से दोषियों के विरुद्ध आरोप व आधार पत्र मंगवाए थे। इंदौर के अफसरों ने इसमें देरी की तो 1 अप्रैल 2019 को परियोजना संचालक ने अर्द्धशासकीय पत्र भी जारी किया था। तब आरोप व आधार पत्र भोपाल भेज दिए थे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले में जब आनंद राणे से बात की तो उनका कहना था कि मैं तो भूल गया हूं। मुझे याद नहीं कि मेरे खिलाफ क्या मामला है।

आनंद प्रकाश राणे

> मुझसे जो दस्तावेज मांगे गए थे, वो मैंने लोकायुक्त को पहुंचा दिए थे। जांच वहीं चल रही है। **एके चटर्जी**, तत्कालीन संभागीय परियोजना यंत्री पीआईयू इंदौर (अब भोपाल में पदस्थ)

> शिकायतें काफी हद तक सही थीं। मैंने जांच कर रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद शासन की तरफ से ही आरोप तय होना थे। **केके लच्छे**, तत्कालीन जांच अधिकारी पीआईयू

Badri Gautam

कोरोना पाजीटिव छोड़, प्रोफेसरों को छुट्टी लेने मेडिकल बोर्ड भेज रहीं प्राचार्य

भोपाल। गीतांजली कॉलेज में करीब डेढ दर्जन प्रोफेसर, कर्मचारी और शिक्षक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना का उपचार कराने के कारण वे कोरोना संक्रमित होने की सूचना कालेज नहीं भेज पाए हैं। इसके चलते प्राचार्य अल्का डेविड ने प्रोफेसरों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। नोटिस से प्रोफेसरों बौखला गए हैं। वे प्राचार्य की शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्य डेविड की दो बिंदुओं पर जांच करने का दायित्व भोपाल होशंगाबाद संभाग के अतिरिक्त संचालक महेंद्र सिंह रघुवंशी को सौंप दिया है।

हालांकि वे अभी तक जांच पूरी नहीं कर सके हैं। अभी तक प्राचार्य डेविड व्हाटसअप ग्रुप पर कोरोना पाजिटिव होने की रिपोर्ट देख रहीं थीं। रविवार से उन्होंने ईमेल पर रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। यहां तक उन्होंने रिपोर्ट को दरकिनार कर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। जब प्रोफेसर बोर्ड में पहुंचे तो उन्हें ये कहते हुए वापस कर दिया है कोरोना में विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। इसमें बोर्ड की जरूरत नहीं होती है।

दस फीसदी स्टाफ का आदेश नदारद

शासन ने दस फीसदी स्टाफ के साथ संस्थान खोलने के आदेश जारी कर रखे हैं। इसके बाद भी प्राचार्य डेविड पचास फीसदी स्टाफ को रोटेशन में बुला रही हैं। इसके कारण प्रोफेसर और कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसके चलते कुछ प्रोफेसरों ने प्राचार्य डेविड पर एक्शन लेने के लिए विभाग और जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसमें वे प्राचार्य डेविड के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

ये ले रहे उपचार

कालेज में पदस्थ प्रोफेसर, कर्मचारी, अतिथि विद्वान कोरोना पॉजिटिव होकर अपना इलाज करा रहे हैं। इसमें डॉ आशा किरण गौर, डॉ सरोज यादव, डॉ आरएस चंदेल, डॉ शिप्रा राय, डॉ प्रेरणा आजाद, डॉ शैलजा सोनी, डॉ गीता प्रभाकर, डॉ पपिहरा अग्रवाल, डॉ साधना गाँधी, डॉ जयश्री मिश्रा, डॉ आराधना वर्मा, डॉ अफ्रिदा हाश्मी (अतिथि विद्वान), गोपाल बाथम लेखापाल और रामनाथ लोधी शामिल है। इसक पहले डॉ मनीषा पाठक, डेनियल डैनी और कु रेखा खैरवार लेब तकनीशियन उपचार लेकर स्वस्थ्य हो चुकी हैं।

प्रोफेसर लंबे समय से गायब थे। इसलिए उनसे कोरोना की रिपोर्ट मांगी गई है। इसकी सूचना विभाग को भेज दी गई है।

डॉ. अल्का डेविड
प्राचार्य, गीतांजलि कालेज

Badri Gautam

इस बार भी महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू होना मुश्किल

अगले सत्र के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं की कार्यवाही

रीवा। जिले के सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालय में इस बार भी नये पाठ्यक्रम शुरू होना मुश्किल लग रहा है। आगामी सत्र में नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने मान्यता कार्यवाही ठप है। उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र के लिए मान्यता आवेदन कार्यवाही को अब तक गति नहीं दी है। ऐसे में अगले सत्र में भी छात्रों के लिए नये पाठ्यक्रम शुरू होने की सम्भावना नहीं दिख रही। कोरोनाकाल के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। बता दें कि पिछले सत्र में कोरोना के चलते विभागीय कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तब भी विभाग ने किसी भी महाविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने पर रोक लगा दी थी। अब लगातार दूसरे साल कोरोना संक्रमण ने ऐसी विभागीय कार्यवाही पर विराम लगा दिया है। गौरतलब है कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय रीवा अंतर्गत 71 सरकारी महाविद्यालय हैं। आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष महाविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने विभाग के समक्ष प्रस्ताव भेजते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत जिले के महाविद्यालयों ने विभाग के समक्ष नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मान्यता व सम्बद्धता कार्यवाही नहीं हो सकी है।

Badri Gautam

छात्रों की भीड़ नियंत्रित करने की कोशिश

बता दें कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी को रोकने जिले में विगत 15 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लागू हैं, लिहाजा शैक्षणिक संस्थान बंद है। और अभी जिले के शैक्षणिक संस्थान अगले 1 माह बंद रह सकते हैं। यदि दो माह बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती भी है तो विभाग के लिए पहली चुनौती छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाना होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए ही विभाग ने फिलहाल नए पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार नहीं किया है।

बीबीए: 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन का आज आखिरी दिन

भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की बीबीए, होटल मैनेजमेंट प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की तारीख समाप्त हो गई है। वहीं 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ सोमवार को आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा यूजी-पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए भी सामान्य शुल्क के साथ 3 मई तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

बीयू

Badri Gautam

मैनिट में स्थिति सामान्य होने पर तय होगी एंड टर्म एग्जाम की तारीख

एजुकेशन

भोपाल। मैनिट की परीक्षाओं पर भी कोरोना का असर पड़ रह है। हालांकि संस्थान ने एंड टर्म एग्जाम की तारीख स्थिति थोड़ी सामान्य होने पर करने का फैसला लिया है। मैनिट में अब 9 मई तक मिड सेमेस्टर ब्रेक लगाया गया है। इसी के साथ मिड टर्म एग्जाम 10 से 15 मई के बीच होंगे। मैनिट प्रबंधन ने सभी छात्रों को निर्देशित किया है कि यदि वे कोरोना पॉजिटिव हैं तो इस संबंध में एचओडी को सूचित करें। इसी के साथ उन्हें संबंधित दस्तावेज भी भेजने होंगे।

Badri Gautam

शिक्षक दाह संस्कार के साथ अस्थि विसर्जन भी करवाएंगे

■ धार जिले में कलेक्टर ने मनावर से की शुरुआत
■ कई अन्य जिलों में भी शिक्षक कर रहे यह मानवीय कार्य

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना ड्यूटी कर रहे शिक्षक अब श्मशान घाट में दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन का काम भी करवाएंगे। राज्य के धार जिले से यह शुरुआत की गई है।

यहां के मनावर विकासखंड में कलेक्टर द्वारा श्मशान घाटों पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि विकासखंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक कोरोना से मृत लोगों का दाह संस्कार करवाएंगे। इसके बाद उन्हें अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया भी पूरी करवानी होगी। जारी आदेश के अनुसार इस कार्य में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उनमें नटवर यादव कमल निर्गुणी प्रवीण शर्मा पवन कुमार सेंधव महेश कुमार सूर्यवंशी विजय शर्मा सज्जाद खान एवं जय सिंह चौहान शामिल है। यह सभी शिक्षक तहसील धरमपुरी के हैं। कलेक्टर द्वारा इन्हें दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन करवाने की जवाबदारी सौंपी गई है। इधर यह भी बताना होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी शिक्षक पहले से ही यह मानवीय कार्य करते हुए कोरोना के संकट काल में जन सेवा की मिसाल कायम कर रहे हैं।

स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को करना चाहिए यह कार्य

शिक्षकों की दाह संस्कार एवं अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में ड्यूटी लगने से शासकीय अध्यापक संगठन का वक्तव्य आया है। संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल का कहना है कि अभी तक कोरोना में दिवंगत लोगों के शवदाह संस्कार की क्रिया पूरी कराने का काम स्थानीय निकाय के कर्मचारी करते रहे हैं। शिक्षकों को इस कार्य में लगाना समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या चाहता है। उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षकों के साथ कोई अनहोनी घटित होती है तो फिर इसका जवाब दार कौन होगा। उन्होंने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पंचायतों के कर्मचारी एवं पुलिस की मौजूदगी में यह काम होना चाहिए। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कर्मचारी एवं पुलिस जवानों के की मौजूदगी में दाह संस्कार का काम करवाती रही है। वर्तमान में भी यही व्यवस्था हो तो बेहतर होगा।

Badri Gautam

सीए परीक्षा के लिए कल से फिर ओपन होगी एप्लीकेशन विंडो

नई दिल्ली, जेएनएन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए मई 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो दोबारा ओपन करेगा। ऐसे में जो कैंडिडेट्स अभी तक सीए मई परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में आईसीएआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी। इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी वजह से परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं, वे 4 मई से एक बार फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो ■ शेष पृष्ठ 9 पर

अब 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स

Badri Gautam

कलेक्टरों ने पलट दिए योद्धा योजना के आदेश

पंचायत विभाग में सहायकों से लेकर सचिव एवं अधिकारियों को मिलना था लाभ

भोपाल(आरएनएन)। सिस्टम कितना लाचार और लड़खड़ा चुका है। सरकार द्वारा जिलों में जारी आदेशों से यह हकीकत पता चलती है। कोरोना की दूसरी लहर में फिर से राज्य सरकार ने पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का लाभ देने के लिए आदेश जारी किए थे। हास्यपद है कि सरकार के इन आदेशों को कई जिलों में कलेक्टर ने मानने से इनकार कर दिया है। पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के 52 हज़ार ग्रामों में पंचायत सचिव रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किए थे। कारण भी है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए इस मैदानी महकमें को अनेक जवाबदारी सौंपी गई है। इसमें कोरेन्टाइन, खाने की व्यवस्था, टीका लगवाना, मेडिकल किट बंटवाना पंचायत दर्पण पोर्टल में फीड करना, बैरियर लगवाना, लगातार कंट्रोल रूम में सूचना देना, कहीं कहीं कोरोना द्वारा मृतक की अंत्योष्टि भी करने की जवाबदारी भी इन्हें सौंपी गई है।

इसके अलावा प्रवासियों की सूची श्रमिक पोर्टल में अपडेट करना और संक्रमण के बाद भी नरेगा प्रगति कोरोना संक्रमण के दौरान उक्त कार्य सुचारू रुप से संपादित कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधीन पदस्थ अधिकारी कर्मचारी पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक समन्वय अधिकारी सहायक विस्तार अधिकारी संविदा आउटसोर्सकर्मी तथा अनुबंधित दैनिक वेतनभोगी को मुख्यमंत्री कोविड.19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत कोरोना योद्धा घोषित किये जाने हेतु समस्त कलेक्टर को पत्र भेजा गया था।

Badri Gautam

भगवान भरोसे सेवा कर रहे हैं सचिव और सहायकः शर्मा

मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने कहा है कि पंचायत सचिव रोजगार सहायक और अन्य अधिकारी कर्मचारी इस समय भगवान भरोसे ग्रामों में जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आरोप लगाया है कि सरकार ने सचिवों एव सहायक सचिवों के लिए ना बीमा की व्यवस्था की है। ना ही पेंशन की कोई पात्रता की है। रोजगार सहायक एवं सचिवों का आरोप है कि कोरोना योद्धा की पात्रता से भी हमें अलग कर दिया है। ऐसी स्थिति में हम अपने परिवार को अंधकार में नही डाल सकते। जब तक पंचायत सचिवों एवम सहायक सचिवों को कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया जाता है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि कोरोना में जनता की सेवा करते हुए कई पंचायत सचिव और रोजगार सहायक शहीद हो गए हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है। नाही दिवंगत सचिव और सहायकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

कई जिलों में कलेक्टरों ने आदेश पलटकर बढ़ाई चिंताः परमार

मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार ने आरोप लगाया है कि कई जिलों में कलेक्टर ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया है। कुछ जिले के कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी कर दिऐ गये कुछ कलेक्टर द्वारा आज तक घोषित नहीं किया गया। परमार का आरोप है कि पन्ना, रीवा एवं बैतूल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश निरस्त कर दिया है। कोरोना संक्रमण एवम ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से प्रदेश भर में 20 से अधिक पंचायत सचिवों एवं अन्य संविदा कार्मिकों एवं कार्मिकों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कोविड.19 योद्धा घोषित ना करना सिस्टम की कमजोरी को दर्शा रहा है। आदेश में विभाग के कार्मिकों को मुख्यमंत्री कोविड.19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत पात्र कर्मी घोषित किया था। आदेश जारी करके निरस्त करने से ग्राम पंचायतों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी आहत हुए है।

कोरोना मरीजों की सेवा करते मेडिकल की नर्स शहीद

55 लाख मुआवजे और कोरोना योद्धा सम्मान को लेकर हंगामा

जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड मरीजों की सेवा करने वाली नर्सिंग योद्धा रविवार सुबह कोविड से लड़ते-लड़ते जंग हार गई। मौत के बाद नर्सेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 55 लाख रुपये मुआवजा, शव को तिरंगा में लपेटकर कोरोना योद्धा सम्मान देने तथा अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्टाफ नर्स मीना सराठे की ड्यूटी 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के लिए पेईंग वार्ड में मरीजों की सेवा के लिए लगाई गई थी। 18 अप्रैल को उन्होंने जब अपना कोविड टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई, इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती किया गया। हालात गंभीर होने पर उन्हें चिकित्सकों ने सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन लगातार स्थिति बिगड़ने के बीच रविवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।

Badri Gautam

डायबिटीज और थायराईड से भी पीड़ित

नर्सेस स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष सुनीला ईशदीन का कहना है कि महामारी की भेंट चढ़ी स्टॉफ नर्स मीना को थायराईड और डायबिटीज की बीमारी थी। उन्हें कोविड के लिये वैक्सीन भी नहीं लगाई गई थी। जब उनकी डयूटी कोविड वार्ड में लगाई गई थी, तब उन्होंने अपनी बीमारी और वैक्सीनेशन नहीं होने की दलील देते हुये कोविड वार्ड में डयूटी न लगाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।

सम्मान से निकली अंतिम यात्रा

खुद बीमार होने के बाद के बाद भी अंतिम समय तक कोविड पेशेंट की सेवा में लगी रहीं, सिस्टर मीना के निधन के बाद मर्चुरी के सामने नर्स एवं स्टॉफ उपस्थित हुये. उनके बलिदान पर श्रृध्दांजलि दी, जिसके बाद शव को तिरंगा लगी गाड़ी में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई।

एसबीआई में 5,454 पदों पर निकाली भर्ती

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने 5,454 पदों पर नौकरियां निकाली हैं। जो युवा बैंक में नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये एक मौका है। परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें।

Badri Gautam

बीएड-एमएड की काउंसिलिंग : आठ तक देनी है जानकारी

इंदौर। अगले सत्र में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त कालेजों को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। यह काम आठ मई तक पूरा करना है ताकि बीएड-एमएड सहित अन्य कोर्स की काउंसिलिंग के दौरान कालेजों को प्रवेश सूची में शामिल किया जा सके। वहीं विभाग ने कालेजों की संबद्धता के सत्यापन के लिए 15 मई तक का समय रखा है। माना जा रहा है कि जुलाई से पहले इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आनलाइन काउंसिलिंग शुरू हो सकती है। फरवरी में विभाग ने मई से एनसीटीई मान्यता प्राप्त बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएससीबीएड, बीएलएड, बीएबीएड कोर्स की काउंसिलिंग शुरू करने का फैसला लिया था।

Badri Gautam

पीएम की तैयारी : इन छात्रों को बाद में भर्ती में छूट की उम्मीद

एमबीबीएस, नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की कोरोना ड्यूटी लगाई जा सकती है

एजेंसी . नई दिल्ली | देश में कोरोना की दूसरी लहर के घातक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विशेषज्ञों के साथ समीक्षा की। इसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और डॉक्टरों तथा नर्सों की कमी को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन शुरू हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। इनके अनुसार, सरकार नीट (पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) स्थगित कर सकती है। एमबीबीएस व नर्सिंग के पासआउट तथा अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं की कोरोना ड्यूटी लगाई जा सकती है।

आज ऐलान संभव : सरकार आर्थिक प्रोत्साहन देगी, नीट टलने के आसार

सूत्रों की मानें तो सरकार ऐसी ड्यूटी करने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के साथ ही बाद में सरकारी अस्पतालों की भर्ती में विशेष छूट दे सकती है। इसकी घोषणा सोमवार को हो सकती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के मुद्दे की समीक्षा की। कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों, ऑक्सीजन निर्माताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकें की हैं। पिछले दिनों सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

Badri Gautam

कोविड ड्यूटी : मेडिकल और नर्सिंग विद्यार्थियों को मानदेय

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इस दौरान

जिन संभावित कदमों पर चर्चा हुई, उनमें चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों या पास कर चुके छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन (मानदेय) देना भी शामिल है। बैठक में आक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, इन कदमों के संबंध में सरकार सोमवार को विस्तृत जानकारी जारी कर सकती है। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि निर्णयों में नीट टालने व एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल हो सकता है। अंतिम वर्ष के एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों की भी इस अभियान में सेवा लेने का फैसला किया जा सकता है। कोविड-19 के काम में जुटे चिकित्साकर्मियों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जा सकती है।

बड़ा फैसला

- कोरोना ड्यूटी वालों को सरकारी भर्तियों में वरीयता देने पर विचार
- पीएम मोदी ने की आक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा

बिहार में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मान होगा वैक्सीनेशन

पटना (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को निर्देश दिया कि बिहार में मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर टीकाकरण कराया जाएगा।

ओडिशा : सीएम पटनायक ने पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स घोषित किया है। पत्रकार की मृत्यु पर स्वजन को 15 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

Badri Gautam

प्रयास | **11 आश्रयगृहों के बच्चों के लिए योग व प्राणायाम के साथ दिया जा रहा सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण**

बच्चों में रचनात्मक कार्यों से दूर कर रहे कोरोना का भय

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना का भय हर किसी में व्याप्त है। खासतौर से बच्चों में भी कोरोना का डर नजर आ रहा है। इस कारण राजधानी के आश्रयगृहों में रह रहे बच्चों को कोरोना के डर और अवसाद से बचाने के लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) बच्चों को रचनात्मकता से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए समिति ने एक इवेंट कैलेंडर तैयार किया है। राजधानी के 11 आश्रयगृहों के बच्चों के लिए योग व प्राणायाम के साथ सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों को टास्क में इनडोर गेम्स के साथ ही पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, कुकिंग और अन्य रचनात्मक कार्य सिखाया जा रहा है। साथ ही बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए काउंसिलिंग और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को भी दिनचर्या में शामिल किया गया है। इस संबंध में सीडब्ल्यूसी सदस्यों का कहना है कि प्रयास है कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ और तनाव मुक्त रहें। इसके तहत आश्रयगृह में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों में सकारात्मक उर्जा बनी रहे। साथ ही बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आश्रयगृह में इन दिनों बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

आश्रयगृह में बच्चों को योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ● नवदुनिया

Badri Gautam

ऑनलाइन करा रहे योग व काउंसिलिंग

आश्रयगृह के बच्चों को मानसिक संबल देने के लिए काउंसलर की व्यवस्था की गई है। काउंसलर द्वारा बच्चों की ऑनलाइन काउंसिलिंग की जा रही है। इसके अलावा समिति के सदस्य भी सभी स्टॉफ मेंबर्स और बच्चों से रोज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को समझा जा सके। हर रोज सुबह आठ से नौ बजे तक बच्चों के लिए योग व प्राणायाम आयोजित किया जा रहा है। बच्चों के लिए पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं, जिससे बच्चों का मन इनमें लगा रहे।

नियमित किया जा रहा है हेल्थ चेकअप: बच्चों का रेग्यूलर हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। बच्चों को आहार विशेषज्ञ के माध्यम से घरेलू व औषधीय चीजों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जानकारी दी जा रही है।

आश्रयगृह के बच्चों की काउंसिलिंग कराए जाने पर यह बात सामने आई कि उनमें कोरोना का भय व्याप्त है। साथ ही वे अवसाद ग्रसित हो रहे है। उन्हें मोटिवेट करने के लिए रचनात्मक कार्य दिए जा रहे हैं। – **डॉ. कृपाशंकर चौबे**, सदस्य सीडब्ल्यूसी

केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अभी तारीख तय नहीं

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। देशभर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में चल रही पहली कक्षा से लेकर नौवीं तक की प्रवेश प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में केवीएस की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। संयुक्त आयुक्त की ओर से केंद्रीय विद्यालयों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह नोटिस भेजा गया है। इसमें लिखा है कि पहली कक्षा के लिए एडमिशन की घोषणा 23 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन फिर इसे 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान आवेदन प्रक्रिया की सूची निकालकर अभिभावकों को एडमिशन की सूचना दी जानी थी, लेकिन अभी तक कोई तिथि तय नहीं है। वहीं दूसरी से लेकर नौवीं तक की एडमिशन लिस्ट जारी करने का निर्णय संबंधित राज्यों के संयुक्त आयुक्त द्वारा किया जाएगा। संबंधित राज्य में कोविड-19 के हालात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला होगा।

Badri Gautam

नौवीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी

नोटिस के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा नौवीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है, लेकिन इस बार केवीएस ने यह प्रवेश परीक्षा रद कर दी है। अन्य कक्षाओं की तरह ही प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन दिए जाएंगे।

शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत

संत हिरदाराम नगर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है। संत हिरदाराम कालेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों ने यह बात कही। मुख्य वक्ता डॉ. निखिलेश प्रधान ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विश्व स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई परिवर्तन करने की जरूरत है। छात्रों के कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने कहा कि वेबिनार के माध्यम से शिक्षा नीति में जरूरी सुझाव एकत्रित करना एवं इसके क्रियान्वयन के प्रयास करना है। समय तेजी से बदल रहा है इसलिए बदलाव भी तेजी से हो रहे हैं।

Badri Gautam

बीयू से संबद्ध 280 कॉलेजों की संबद्धता हो सकती है समाप्त

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) ने बोर्ड ऑफ स्टडी गठित करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए विवि से संबद्ध निजी कॉलेजों से वहां मौजूद फैकल्टी की जानकारी मांगी है। हालांकि निजी कॉलेजों ने अभी आधी-अधूरी जानकारी भेज दी है। इसके लिए बीयू ने कॉलेजों को नोटिस देकर एक माह के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक कॉलेजों ने स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं। लिहाजा विवि ने एक मौका और देते हुए कॉलेज संचालकों को 15 दिन में पूरी जानकारी देने को कहा है। इसके बाद मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, विवि को कॉलेजों में मौजूद फैकल्टी की संख्या में फर्जीवाड़ा होने की शिकायत मिली थी। जिसके चलते विवि से संबद्धता प्राप्त 280 कालेजों से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और प्राचार्यों की संख्या मांगी गई थी। इसके उन्हें नोटिस भेजे गए थे, जिसकी जानकारी कालेजों को एक माह में देनी थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब बीयू उनकी संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही करेगा। इसके चलते वे आगामी सत्र 2021-22 में प्रवेश देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की काउंसिलिंग में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए कालेज संचालकों को अपने कालेज में पदस्थ प्राचार्य, एचओडी और प्रोफेसरों की पूरी जानकारी भेजना है, क्योंकि निजी कालेजों में विद्यार्थियों ने प्रवेश तो लिया है, लेकिन प्राचार्य, एचओडी और अध्ययन कराने वाले प्रोफेसर ही नियुक्त नहीं हैं। यहां तक यूजीसी के मापदंडों के मुताबिक विद्यार्थियों के अनुपात में प्रोफेसरों को नहीं रखा गया है। ऐसे कालेजों को संबद्धता समाप्ति से पहले अपना पक्ष रखने के लिए फिर से नोटिस भेजे गए हैं। कालेजों को 15 दिन के भीतर इसका जवाब भेजना है।

सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के नाम भी शामिल

निजी कालेजों के प्रोफेसर नौकरी छोड़ चुके है। वेतन ज्यादा होने के कारण कालेज संचालकों ने उन्हें बाहर कर दिया है और उनकी जगह कम वेतन में दूसरे व्यक्ति को रख लिया है। कालेज संचालकों ने दोनों प्रकरणों की सूचना बीयू को नहीं भेजी है। वहीं कालेजों से सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसरों के नाम भी दस्तावेजों में चलाए जाने की बात सामने आई। जबकि उनके स्थान पर आठ से दस हजार रुपये के मासिक वेतन पर लोगों को रख लिया गया है।

हर तीन साल पर गठित होता है: विवि द्वारा हर तीन साल पर बोर्ड ऑफ स्टडी गठित की जाती है। इसमें वरिष्ठ प्रोफेसरों व प्राचार्यों को शामिल किया जाता है। 2016 के बाद विवि ने बोर्ड ऑफ स्टडी को गठित नहीं किया। बोर्ड ऑफ स्टडी एकेडमिक कार्यों की रूपरेखा तय करता है। यह बोर्ड विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का निर्धारण, परीक्षा संबंधी और सिलेबस सबकुछ तय करता है।

कालेजों से प्रोफसरों, प्राचार्यों व डीन सहित विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी मांगी गई है। अब कालेज समयसीमा में नोटिस का जवाब नहीं देते है तो नियमानुसार उनकी संबद्धता समाप्त की जाएगी।

– **डॉ. एचएस त्रिपाठी**, रजिस्ट्रार, बीयू

Badri Gautam

बीयूः 210 प्राइवेट कॉलेजों ने नहीं दिया नोटिस का जवाब, हो सकती है कार्रवाई

फैकल्टी के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला, जवाब देने 31 मई तक मौका

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) से संबद्धता प्राप्त 280 कॉलेजों में फैकल्टी के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायतों पर इन कॉलेजों को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई थी। लेकिन इनमें से केवल 70 कॉलेजों ने ही नोटिस का जवाब दिया। शेष 210 कॉलेजों के पास 31 मई तक का आखिरी मौका है। इसके बाद इन कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। संबद्धता समाप्त होने पर ये कॉलेज सत्र 2021-22 में प्रवेश देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की काउंसलिंग में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। इन

कॉलेजों में कोड-28 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और प्राचार्य नहीं हैं। कई कॉलेज तो ऐसे हैं, जिनमें वर्षों से प्राचार्य व एचओडी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन दस्तावेजों में उनका नाम है। यूजीसी के मापदंडों के मुताबिक विद्यार्थियों के रेशो में प्रोफेसर भी नहीं रखे गए हैं। इसकी शिकायत मिलने पर रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी ने कॉलेजों को नोटिस भेजे थे।

इसलिए नहीं दे रहे जानकारी

अधिकांश कॉलेजों में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं हो रहा। इसलिए वे बीयू को जानकारी देने से कतरा रहे हैं। स्थिति यह है कि कई प्रोफेसर निजी कॉलेजों में नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें बाहर कर दिया गया है और कम वेतन में दूसरे को रख लिया है। लेकिन दस्तावेजों में वर्षों से उन्हीं क्वालीफाई प्रोफेसरों के नाम चल रहे हैं।

कॉलेजों में स्टूडेंट्स के रेशो के अनुसार दी जा रही सुविधाएं और प्रोफेसरों, प्राचार्यों की नियुक्तियों की जानकारी देने के लिए नोटिस दिए गए थे। लगभग 70 कॉलेजों के जवाब आ गए हैं। बाकी समयसीमा में जवाब नहीं देते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. एचएस त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू

Badri Gautam

कोरोनाकाल में प्रभावित हो रहा शोध कार्य

परीक्षकों को बुलाने व साक्षात्कार की प्रक्रिया में लॉकडाउन का व्यवधान

कर्मचारी कम होने से विश्वविद्यालय को हो रही दिक्कत

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नामांकित शोधार्थियों का शोधकार्य कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन के चलते प्रभावित हो रहा है। शोधार्थियों की थीसिस समय पर विश्वविद्यालय में जमा नहीं हो पा रही है। जिन शोधार्थियों की थीसिस जमा हो भी गई है, उनके साक्षात्कार की प्रक्रिया की रूकी है। परीक्षकों को बुलाने बाबत पत्र जारी करने की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हालांकि विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यवाही को गति देना चाह रहा है परंतु लॉकडाउन में कर्मचारी कम होने से दिक्कत हो रही है। शासन के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू के 5 दिनों में 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ ही विश्वविद्यालय काम कर रहा है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विश्वविद्यालय में मौजूदा 10 प्रतिशत स्टाफ के होने पर स्थिति और खराब हो गई है। अब विश्वविद्यालय के सामान्य परीक्षा, शोध कार्य जैसे कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं। वहीं, छात्रों की परेशानी भी बढ़ी हुई है।

गौरतलब है कि गत वर्ष भी 25 मार्च से केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था। कोरोना संक्रमण को रोकने यह पूर्णतः लॉकडाउन

जून तक प्रभावी रहा। इसके बाद भी शैक्षणिक व शोध गतिविधियां प्रभावित रहीं। तब विश्वविद्यालय के स्थानीय टीचर एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखा था। पत्र में एसोसिएशन ने थीसिस व अन्य शोध कार्य को जमा करने की तिथि में इजाफा करने की मांग उठाई गई थी। वहीं स्थिति एक बार फिर निर्मित होने लगी है।

थीसिस जमा करने में कठिनाई

जिन शोधार्थियों का शोध कार्य अप्रैल 2021 में जमा होना था। वह लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू के चलते विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पा रहे। यदि किसी तरह शोधार्थी विश्वविद्यालय पहुंच भी जाते हैं तो शोध कार्य जमा होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में शोधार्थियों का बेजा नुकसान हो रहा है और उनका निर्धारित समय गुजरा जा रहा है। बताते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंटर में व अकादमिक भवन में एक-एक कर्मचारी उक्त कार्य के लिए बैठाया है परंतु परिवहन असुविधा, समयाभाव, कोरोना या अन्य कारणों से उक्त प्रक्रिया सुचारू ढंग से अभी सम्पन्न नहीं हो पा रही है।

जिनकी आरडीसी हुई, उन्हें अनुमति पत्र नहीं हुआ जारी

विदित हो कि विश्वविद्यालय ने गत मार्च-अप्रैल माह में पीएचडी अभ्यर्थियों की आरडीसी कराई थी। करीब 30 विषयों के एक हजार अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। अब जिन अभ्यर्थियों की आरडीसी हो गई है, उनको थीसिस लिखने अनुमति पत्र जारी नहीं हो सके हैं। महीने भर से अभ्यर्थी पत्र का इंतजार कर रहे हैं। इधर, कर्मचारियों की कमी से उक्त कार्यवाही भी विश्वविद्यालय में रूकी हुई है। हालांकि आरडीसी कार्यवाही का अनुमोदन होने की जानकारी है। अब केवल पत्र जारी होना शेष रह गया है। बताते चलें कि जो अभ्यर्थी उक्त आरडीसी व पंजीयन प्रक्रिया से वंचित रह गए थे, उनके विश्वविद्यालय ने फिर से ऑनलाइन पंजीयन हेतु पोर्टल खोल दिया है। अभ्यर्थी 15 मई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। फिर पंजीकृत अभ्यर्थियों को 21 मई तक विश्वविद्यालय में आवेदन की हार्डकॉपी जमा करनी होगी। तदुपरांत पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु आरडीसी कराई जायेगी।

Badri Gautam